भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारां कत प्रश्न सं.407
दिनांक 23 मार्च, **2020**

जैव ईंधन नीति, **2018**

407. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शंदेः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार ने वर्ष, **2018** में नई जैव ईंधन नीति लागू की है;
(ख) जैव ईंधन बनाने की नीति को आगे बढ़ाते हुये प्राप्त आशय पत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें जैव ईंधन के प्रकार को वर्गीकृत कया गया है;
(ग) क्या सरकार द्वारा जैव ईंधन नीति, **2018** में यथाव र्णत इथेनॉल म श्रत पेट्रोल बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) जैव ईंधन नीति, **2018** का कार्यान्वयन करने हेतु आवंटित बजट तथा इस संबंध में अब तक व्यय की गई रा श का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या इस नीति के अंतर्गत नियम बनाये गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा नियमों का प्रारूप तैयार करने का कार्य वर्तमान में कस चरण पर है**?**

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ड.): एक ववरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"जैव ईंधन नीति, **2018"** के संबंध में संसद सदस्य डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शंदे और श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा पूछे गए दिनांक 23 मार्च, 2020 के लोक सभा तारां कत प्रश्न सं. 407 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लि खत ववरण।

(क) से (ग) सरकार ने 04 जून, 2018 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 को अ धसू चत कया है। इस नीति में वर्ष 2030 तक पूरे देश में पेट्रोल में 20**%** एथेनॉल का मश्रण तथा डीजल में 5**%** जैव डीजल का मश्रण करने का निर्देशात्मक लक्ष्य हा सल करने की परिकल्पना की गई है।

सरकार आयात निर्भरता में कमी करने, रोजगार का सृजन करने, कसानों को बेहतर पारिश्र मक प्रदान करने और बेहतर अप शष्ट प्रबंधन पद्धतियों आदि के व्यापक उद्देश्यों से जैव ईंधन कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है।

एथेनॉल म श्रत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की अ धप्राप्ति एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) (01 दिसम्बर से 30 नवम्बर) 2013-14 के दौरान 38 करोड़ लीटर से लगभग पांच गुना बढ़कर ईएसवाई 2018-19 के दौरान 188.6 करोड़ लीटर हो गई है। मश्रण के लए एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्न ल खत शा मल हैं:-

(i) गन्ना रस और चीनी/चीनी सीरप से एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देना।

(ii) व भन्न प्रकार के फीड स्टॉक से उत्पादित एथेनॉल का मल तक का लाभकारी मूल्य निर्धारित करना।

(iii) आसवनियों को ब्याज इमदाद प्रदान करना।

(iv) एथेनॉल म श्रत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लए वकृत एथेनॉल की स्वतंत्र रूप से आवाजाही के लए उद्योग (वकास और वनियमन) अ धनियम, **1951** में संशोधन।

(v) ईबीपी कार्यक्रम के लए निर्धारित एथेनॉल पर माल और सेवा कर को 18**%** से घटाकर 5**%** करना।

(vi) दिनांक 01.04.2019 से अंडमान निकोबार तथा लक्षदीप के संघ शा सत प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में ईबीपी कार्यक्रम लागू करना।

(vii) तेल वपणन कंपनियों के स्थलों पर एथेनॉल के भंडारण को बढ़ाना।

(viii) "एथेनॉल म श्रत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत दीर्घका लक आधार पर एथेनॉल अ धप्राप्ति नीति" तैयार करना।

ईएसवाई 2019-20 में, दिनांक 09.03.2020 तक, तेल वपणन कंपनियों (ओएमीसज) ने 156.47 करोड़ लीटर एथेनॉल की अ धप्राप्ति के लए आशय-पत्र (एलओआई) जारी कए हैं।

सरकार ने एथेनॉल की आपूर्ति को और अ धक बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रो रसायन रूट सहित सेल्यूलो सक तथा लग्नोसैल्यूलॉ सक साम ग्रयों जैसे अन्य गैर खाद्य फीड स्टॉक से उत्पादित दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल की अ धप्राप्ति करने की अनुमति दे दी है। तदनुसार, तेल पीएसयूज ने देश के 11 राज्यों में बारह 2जी एथेनॉल जैव रिफाइनरियां स्था पत करने की योजना बनाई है।

जैव डीजल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जैव डीजल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ) की पहचान भावी कच्चे माल के रूप में की गई है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने 200 स्थलों पर प्रयुक्त खाद्य तेल से उत्पादित जैव डीजल की अ धप्राप्ति के लए रू च की अ भव्यक्ति (इओआई) आमंत्रित की है। प्रयुक्त खाद्य तेल से जैव डीजल का उत्पादन करने के उद्देश्य से 46 संयंत्रों की स्थापना करने के लए ओएमसीज को 29 ईओआई प्राप्त हुई हैं।

ऑटोमोटिव ईंधन के तौर पर संपी डत जैव गैस (सीबीजी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, दिनांक 01.10.2018 को कफायती परिवहन के लए दीर्घका लक वकल्प (सतत) पहल की शुरूआत की गई है, जिसके तहत ओएमसीज सीबीजी उत्पादन के लए संभा वत उद्य मयों से रू च की अ भव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित कर रही हैं। सतत पहल में वर्ष 2023 तक प्रति वर्ष 15 एमएमटी सीबीजी के अनुमानित उत्पादन के साथ पूरे देश में 5000 सीबीजी संयंत्रों को स्था पत करने की परिकल्पना की गई है। दिनांक 15.03.2020 तक, तेल पीएसयूज ने मंगाई गई रू च की अ भव्यक्तियों के प्रत्युत्तर में 493 सीबीजी संयंत्रों को स्था पत करने के लए आशय-पत्र (एलओआई) जारी कए हैं।

(घ): लग्नोसैल्यूलॉ सक बायोमास तथा अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करते हुए देश में दूसरी पीढ़ी की एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लए एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं को वत्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लए सरकार ने मार्च, 2019 में "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" अ धसू चत की है। वर्ष 2018-19 से 2023-24 के लए योजना का कुल वत्तीय परिव्यय 1969.50 करोड़ रुपए है।

(ड.): जैव ईंधन नीति व्यापक तौर पर कार्यनीति और दृष्टिकोण सहित जैव ईंधन कार्यक्रम, इससे जुड़े उपायों और सहायक व्यवस्था, पणधारकों की भू मका, संस्थागत व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आदि के व भन्न पहलुओं को कवर करती है। इस स्तर पर, नियम तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****